



प्रेस विज्ञप्ति

मध्य प्रदेश सरकार डब्ल्यूआरआई और एफओएलयू ने राज्य में किसानों की आजीविका को बढ़ाने और पर्यावरण सततता में वृद्धि के लिए मिलाये हाथ

भोपाल, 14 मार्च 2022 : सतत और पुनर्उत्पादक कृषि पद्धतियों को अपनाने में किसानों की मदद के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (एफडब्ल्यूएडी) ने वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) इंडिया और फूड एंड लैंड यूज कोलिशन (एफओएलयू) इंडिया के साथ हाथ मिलाए हैं। इन पक्षों ने आज राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की उपस्थिति में दो सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य राज्य में एक आदर्श कृषि भूदृश्य के विकास के माध्यम से किसानों की आजीविका और पर्यावरण को सुदृढ़ करना है।

पहले एमओयू के तहत कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग डब्ल्यूआरआई इंडिया द्वारा वित्त पोषित ध्वजवाही अध्ययन 'अप्रोचेस फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया : एग्रो-इकोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड कंसीडरेशंस' के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े और अनुसंधान संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। इस अध्ययन में एक प्रणाली आधारित दृष्टिकोण लाकर, जिसमें पारिस्थितिकी सेवाएं और भूदृश्य कारक जैसे कि पारिस्थितिकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव तथा कृषि और भोजन से जुड़े सहलाभ भी शामिल हों, 'किसानों की आय दोगुनी करने के सम्बन्ध में गठित समिति' की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस अध्ययन में देश भर की उन प्रभावशाली अध्ययनों का मानचित्रण भी किया गया है जो पारिस्थितिकी सेवाओं और उनके आर्थिक महत्व पर केंद्रित हैं और हित धारकों के लिए आवश्यक रूप से एक संदर्भ के रूप में काम कर रहे हैं। इस अध्ययन से नीति निर्धारकों को प्रासंगिक नीतियां बनाते वक्त अधिक सतत समाधान प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस अध्ययनों में राज्य सरकार द्वारा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती विशेष तौर पर ऑर्गेनिक कपास की खेती, मोटे अनाज का उत्पादन, कस्टम ग्रेडिंग और प्रसंस्करण केंद्रों तथा कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रभावशाली उपायों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा।



दूसरे एमओयू के तहत मध्य प्रदेश सतत कृषि कार्यक्रम के तहत एक समन्वयकारी एजेंसी की स्थापना की जाएगी ताकि प्रदेश में विभिन्न कृषि विकास परियोजनाओं की योजना और उनके क्रियान्वयन में तालमेल बनाया जा सके। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन एनएमएसए को केंद्र में रखते हुए समन्वयकारी एजेंसी चुनिंदा स्थानों पर सतत कृषि विकास से संबंधित केंद्र तथा राज्य की अन्य योजनाओं को भी लागू करेगी।

एमओयू पर हस्ताक्षर से संबंधित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कमल पटेल ने इस अवसर पर कहा “कृषि क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से है। सरकार इस कार्यक्रम का खुले दिल से स्वागत करती है क्योंकि यह समय की मांग है। हम इन सहमति पत्रों के सफल क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यूआरआई इंडिया और एफओएलयू गठबंधन के साथ काम करेंगे।”

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएस अधिकारी श्री अजीत केसरी भी मौजूद थे। उनके अलावा एफओएलयू इंडिया के कंट्री कोऑर्डिनेटर जयहरि के. एम., डब्ल्यूआरआई इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मधु वर्मा और डब्ल्यूआरआई इंडिया के सस्टेनेबल लैंडस्केप एंड रीस्टोरेशन शाखा की निदेशक डॉक्टर रुचिका सिंह भी उपस्थित थीं।

डब्ल्यूआरआई इंडिया के बारे में

डब्ल्यूआरआई इंडिया एक शोध संस्थान है। इससे सम्बन्धित विशेषज्ञ और स्टाफकर्मों एक स्वस्थ पर्यावरण को बनाये रखने के लिये बड़े विचारों को जमीन पर उतारने के उद्देश्य से नेतृत्वकर्ताओं के साथ जुड़कर काम करते हैं। एक ऐसा स्वस्थ पर्यावरण जो आर्थिक अवसर और मानव कल्याण की नींव है। हम प्राकृतिक संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन द्वारा संचालित एक समान और समृद्ध धरती की कल्पना करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बनाने की आकांक्षा रखते हैं जहां सरकार, व्यापार और समुदायों के कार्य गरीबी को खत्म करने और सभी लोगों के लिए प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं।

एफओएलयू के बारे में

वर्ष 2017 में गठित एफओएलयू ऐसे संगठनों और लोगों का एक समुदाय है जो भोजन को पैदा करने और उसके इस्तेमाल तथा लोगों, प्रकृति और जलवायु के लिए जमीन के प्रयोग को बदलने की तात्कालिक आवश्यकता के प्रति संकल्पबद्ध है। हम विज्ञान आधारित समाधान



का समर्थन करते हैं। साथ ही सामूहिक और महत्वाकांक्षी कदमों को संभव बनाने के लिए चुनौतियों और अवसरों की एक साझा समझ बनाने में मदद करते हैं। भारत में एफओएलयू कॉलीशन में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू), रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क (आरआरएएन), द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई इंडिया) शामिल है। इसमें वह विस्तृत एकीकृत कंट्री मॉडलिंग प्रयास भी शामिल है जो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरईएसएटी) के सहयोग से भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद की अगुवाई में किया गया है। नॉर्वे का पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एफओएलयू कोलीशन का मुख्य सहयोगी है। एफओएलयू के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। [Know more about FOLU here.](#)

श्री जयहरि केएम, पीएचडी

एफओएलयू इंडिया कंट्री कोऑर्डिनेटर

फोन+ :91 9971799271

ईमेल: km.jayahari@wri.org

पल्लवी सिंह

संचार प्रबंधक- एफओएलयू इंडिया

फोन +91 9999154259

ईमेल : pallavi.salut@gmail.com

###